



Lakshya IAS

academy

12

Sep 2026

DAILY CURRENT AFFAIRS



Mr. R.P. Singh Sir
(MD)



1. उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए सरकार ने ई-वाणिज्य नियमों में संशोधन किया

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया है। संशोधित रूपरेखा का उद्देश्य डार्क पैटर्न, भ्रामक खोज हेरफेर और अन्य अनुचित प्रथाओं पर अंकुश लगाना है, जो उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकती हैं। ई-वाणिज्य मंचों की जवाबदेही बढ़ाई जाएगी, जिसमें विक्रेताओं की जानकारी और लाइसेंस की अधिक सख्त जाँच-पड़ताल और सत्यापन शामिल है, विशेष रूप से विनियमित या संभावित रूप से खतरनाक उत्पादों के लिए। संशोधित पारदर्शिता, शिकायत निवारण और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को भी मजबूत करते हैं। संशोधित नियम औपचारिक रूप से 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे, जिससे मंचों को नई आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी प्रणालियों और अनुपालन व्यवस्थाओं को तैयार करने के लिए समय मिलेगा।

मुख्य बिंदु:

- मंचों की अधिक सख्त जवाबदेही: ई-वाणिज्य बाजारों को विशेष रूप से विनियमित उत्पादों के संबंध में अधिक सख्त जाँच-पड़ताल करनी होगी, ताकि वैध उत्पाद सूचीबद्ध हों और उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी दिए जाने से रोका जा सके।

Government Revises E-Commerce Rules to Strengthen Consumer Protection and Transparency

The Ministry of Consumer Affairs has notified amendments to the Consumer Protection (E-Commerce) Rules to strengthen consumer protection and transparency in digital marketplaces. The revised framework aims to curb dark patterns, deceptive search manipulations and other unfair practices that may mislead consumers. E-commerce platforms will face stronger accountability, including greater due diligence and verification of seller credentials and licences, particularly for regulated or potentially hazardous products. The amendments also reinforce transparency, grievance redressal and fair-trade practices. The amended rules will formally come into force from January 1, 2027, giving platforms time to align their systems and compliance mechanisms with the new requirements.

Key Points:

- Stricter platform accountability: E-commerce marketplaces must undertake stronger due diligence, particularly for regulated products, ensuring lawful listings and preventing misleading consumer information.

- विक्रेताओं का अनिवार्य सत्यापन: विनियमित या संभावित रूप से खतरनाक उत्पादों की बिक्री की सुविधा प्रदान करने से पहले मंचों से विक्रेताओं की जानकारी और आवश्यक लाइसेंस का सत्यापन करने की अपेक्षा की जाएगी।
- उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करना: सरकार डिजिटल बाजारों में पारदर्शिता, शिकायत निवारण और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को मजबूत कर रही है, ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित प्रथाओं से सुरक्षित रखा जा सके।

2. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार राज्यों में पाँच रेलवे बहु-पटरी

परियोजनाओं को मंजूरी दी

- ✍ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के रेल बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और परिवहन दक्षता में सुधार करने के लिए



चार राज्यों में पाँच रेलवे बहु-पटरी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेलवे की क्षमता बढ़ाना, व्यस्त मार्गों पर भीड़ कम करना तथा यात्रियों और माल की आवाजाही को अधिक सुचारु बनाना है। बहु-पटरीकरण से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच संपर्क में भी सुधार होगा और तेज तथा अधिक विश्वसनीय रेल परिचालन को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से रसद दक्षता बढ़ने, आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाने और समग्र रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने की उम्मीद है। ये परियोजनाएँ देशभर में रेल क्षमता के विस्तार तथा आधुनिक, कुशल और बेहतर रूप से जुड़े परिवहन बुनियादी ढाँचे के विकास पर सरकार के निरंतर ध्यान को दर्शाती हैं।

मुख्य बिंदु:

- पाँच परियोजनाओं को मंजूरी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच रेलवे बहु-पटरी परियोजनाओं को मंजूरी दी।
- बेहतर संपर्क: परियोजनाएँ संपर्क को मजबूत करेंगी और यात्रियों तथा माल की अधिक सुचारु आवाजाही में सहायता करेंगी।
- आर्थिक लाभ: बेहतर रेल बुनियादी ढाँचे से रसद दक्षता में सुधार और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

- Mandatory seller verification: Platforms are expected to verify seller credentials and required licences before facilitating sales involving regulated or potentially hazardous products.
- Consumer rights strengthened: The government is reinforcing transparency, grievance redressal and fair trade practices across digital marketplaces to protect consumers from unfair practices.

2. Cabinet Approves Five Railway Multitracking Projects Across Four States

- ✍ The Union Cabinet has approved five railway multitracking projects covering four states to strengthen the country's rail infrastructure and improve transportation efficiency. The projects are aimed at increasing railway capacity, reducing congestion on busy routes and enabling smoother movement of passengers and freight. Multitracking will also improve connectivity between important regions and support faster, more reliable train operations. The initiative is expected to enhance logistics efficiency, facilitate economic activity and strengthen the overall railway network. The projects reflect the government's continued focus on expanding rail capacity and developing modern, efficient and better-connected transportation infrastructure across the country.



Key Points:

- Five Projects Approved: The Union Cabinet approved five railway multitracking projects.
- Improved Connectivity: The projects will strengthen connectivity and support smoother passenger and freight movement.
- Economic Benefits: Better rail infrastructure is expected to improve logistics efficiency and support regional economic development.

3. 9वाँ आसियान-भारत कृषि और वानिकी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि पर सहयोग की पुनः पुष्टि करता है

कृषि और वानिकी पर 9वाँ आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सितंबर 2026 में आयोजित किया गया, जिसमें खाद्य-सुरक्षित, टिकाऊ और लचीले कृषि भविष्य के लिए भारत और आसियान के बीच सहयोग की पुनः पुष्टि की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और फिलीपींस के कृषि सचिव ने की। चर्चाओं में व्यावहारिक, किसान-केंद्रित पहलों, कृषि विकास और मजबूत वानिकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। मंत्रियों ने आसियान 2045 और आसियान खाद्य, कृषि और वानिकी क्षेत्रीय योजना 2026-2030 का महत्वपूर्ण मार्गदर्शक रूपरेखाओं के रूप में स्वागत किया। बैठक में कृषि, खाद्य सुरक्षा और सतत संसाधन प्रबंधन में बढ़े हुए सहयोग के माध्यम से आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया।



9th ASEAN-India Ministerial Meeting Reaffirms Cooperation on Food Security and Sustainable Agriculture

The 9th ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry was held in September 2026, reaffirming cooperation between India and ASEAN for a food-secure, sustainable and resilient agricultural future. The meeting was co-chaired by Union Minister Shivraj Singh Chouhan and the Agriculture Secretary of the Philippines. Discussions focused on practical, farmer-centred initiatives, agricultural development and stronger forestry cooperation. Ministers also welcomed ASEAN 2045 and the ASEAN Food, Agriculture and Forestry Sectoral Plan 2026-2030 as important guiding frameworks. The meeting further highlighted efforts to deepen the ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership through enhanced cooperation in agriculture, food security and sustainable resource management



मुख्य बिंदु:

- कृषि सहयोग मजबूत हुआ: भारत और आसियान ने व्यावहारिक, किसान-केंद्रित पहलों के माध्यम से खाद्य-सुरक्षित, टिकाऊ और लचीले कृषि भविष्य के निर्माण के लिए सहयोग की पुनः पुष्टि की।
- रणनीतिक रूपरेखाओं का समर्थन: मंत्रियों ने आसियान 2045 और आसियान खाद्य, कृषि और वानिकी क्षेत्रीय योजना 2026-2030 का मार्गदर्शक रूपरेखाओं के रूप में स्वागत किया।
- वानिकी साझेदारी का विस्तार: चर्चाओं में कृषि और वानिकी सहयोग को मजबूत करने तथा आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

Key Points:

- Agricultural cooperation strengthened: India and ASEAN reaffirmed cooperation for building a food-secure, sustainable and resilient agricultural future through practical, farmer-centred initiatives.
- Strategic frameworks endorsed: Ministers welcomed ASEAN 2045 and the ASEAN Food, Agriculture and Forestry Sectoral Plan 2026-2030 as guiding frameworks.
- Forestry partnership expanded: Discussions focused on strengthening agricultural and forestry cooperation while deepening the ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership.

4. NIELIT डिजिटल विश्वविद्यालय मंच को अमेरिका के सेयलर विश्वविद्यालय के साथ एकीकृत किया गया

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने किफायती ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करने के लिए सेयलर विश्वविद्यालय के डिजिटल शिक्षण संसाधनों को अपने डिजिटल



विश्वविद्यालय मंच के साथ एकीकृत किया है। इस साझेदारी के अंतर्गत, शिक्षार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रोग्रामिंग, आँकड़ा विज्ञान, साइबर सुरक्षा और व्यवसाय प्रबंधन जैसे प्रमुख भविष्य-उन्मुख क्षेत्रों को शामिल करने वाले निःशुल्क, अपनी गति से पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रमों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। यह सहयोग NIELIT की व्यापक राष्ट्रीय पहुँच को सेयलर विश्वविद्यालय के खुले शिक्षण संसाधनों के साथ जोड़ता है, जिससे लचीले कौशल विकास को सक्षम बनाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षार्थियों को प्रासंगिक डिजिटल और व्यावसायिक कौशल से सुसज्जित करना तथा सुलभ ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह भारत के डिजिटल शिक्षण के अवसरों को मजबूत करने और बदलती प्रौद्योगिकी-आधारित रोजगार आवश्यकताओं के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करने के प्रयासों का भी समर्थन करता है।

मुख्य बिंदु:

- डिजिटल शिक्षण एकीकरण: NIELIT ने सेयलर विश्वविद्यालय के डिजिटल शिक्षण संसाधनों को अपने डिजिटल विश्वविद्यालय मंच के साथ एकीकृत किया है, जिससे वैश्विक ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच का विस्तार हुआ है।
- लचीले पाठ्यक्रमों का विस्तार: शिक्षार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रोग्रामिंग, आँकड़ा विज्ञान, व्यवसाय, नेतृत्व और अन्य भविष्य-उन्मुख कौशलों को शामिल करने वाले अपनी गति से पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रमों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।
- वैश्विक कौशल तक पहुँच: यह सहयोग NIELIT की राष्ट्रीय पहुँच को सेयलर के खुले शिक्षण संसाधनों के साथ जोड़ता है, जिससे शिक्षार्थियों के लिए किफायती और लचीले डिजिटल कौशल विकास को समर्थन मिलता है।

4. NIELIT Digital University Platform Integrated with Saylor University of the USA

The National Institute of Electronics and Information Technology has integrated Saylor University's digital learning resources with its Digital University platform to expand access to affordable online education. Under the partnership, learners can access free, self-paced courses covering key future-ready domains such as artificial intelligence, programming, data science, cybersecurity and business management. The collaboration combines NIELIT's extensive national outreach with Saylor University's open-learning resources, enabling flexible skill development. The initiative aims to equip learners with relevant digital and professional skills while promoting accessible online education. It also supports India's efforts to strengthen digital learning opportunities and prepare learners for evolving technology-driven employment requirements.



Key Points:

- Digital learning integration: NIELIT has integrated Saylor University's digital learning resources with its Digital University platform, expanding access to global online education.
- Flexible courses expanded: Learners can access self-paced courses covering artificial intelligence, programming, data science, business, leadership and other future-ready skills.
- Global skills access: The collaboration combines NIELIT's national outreach with Saylor's open-learning resources, supporting affordable and flexible digital skill development for learners.

5. झारखंड में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को लागू करने के लिए बहु-एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर

झारखंड में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण ब्रॉडबैंड बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना और वंचित क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। इसके कार्यान्वयन में सहायता के लिए केंद्रीय एजेंसियों, राज्य प्राधिकरणों और नामित साझेदारों के बीच समन्वय के माध्यम से एक बहु-एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बीएसएनएल को परियोजना प्रबंधन परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए नामित किया गया है। संशोधित कार्यक्रम ग्राम पंचायतों और अतिरिक्त गाँवों के लिए माँग-आधारित कनेक्टिविटी को भी सक्षम बनाता है, जिससे व्यापक डिजिटल समावेशन को समर्थन मिलता है। इस पहल से झारखंड के ग्रामीण और दूरदराज के समुदायों में डिजिटल सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुँच में सुधार होने की उम्मीद है।



मुख्य बिंदु:

- ग्रामीण कनेक्टिविटी पर लक्ष्य: संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रॉडबैंड बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना और ग्रामीण तथा वंचित क्षेत्रों में उच्च गति कनेक्टिविटी का विस्तार करना है।
- बहु-एजेंसी कार्यान्वयन: भारतनेट के कार्यान्वयन में ग्रामीण डिजिटल बुनियादी ढाँचे को तेजी से विकसित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों, राज्य प्राधिकरणों और नामित कार्यान्वयन साझेदारों के बीच समन्वय शामिल है।
- माँग-आधारित कनेक्टिविटी का विस्तार: संशोधित कार्यक्रम माँग के आधार पर ग्राम पंचायतों और अतिरिक्त गाँवों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे व्यापक ग्रामीण डिजिटल समावेशन को समर्थन मिलता है।

5. Multi-Agency Agreement Signed to Implement Amended BharatNet Programme in Jharkhand

The Amended BharatNet Programme in Jharkhand aims to strengthen rural broadband infrastructure and expand high-speed internet connectivity across underserved areas. A multi-agency agreement has been signed to support its implementation through coordination among central agencies, state authorities and designated partners. BSNL has been designated to provide Project Management Consultancy support for executing the programme in the state. The amended programme also enables demand-based connectivity for Gram Panchayats and additional villages, supporting wider digital inclusion. The initiative is expected to improve access to digital services, education, healthcare and economic opportunities across rural and remote communities in Jharkhand.



Key Points:

- Rural connectivity targeted: The Amended BharatNet Programme aims to strengthen broadband infrastructure and expand high-speed connectivity across rural and underserved areas.
- Multi-agency implementation: BharatNet implementation involves coordination among central agencies, state authorities and designated implementing partners to accelerate rural digital infrastructure.
- Demand-based connectivity expanded: The amended programme provides connectivity to Gram Panchayats and additional villages on demand, supporting broader rural digital inclusion.

6. ESTIC 2026 नई दिल्ली में वैज्ञानिकों, नवप्रवर्तकों और तीन नोबेल पुरस्कार विजेताओं को एक साथ लाएगा

✎ ESTIC 2026, एक अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन, 27 से 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाना



निर्धारित है। यह कार्यक्रम विज्ञान और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों, नवप्रवर्तकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को एक साथ लाएगा। तीन नोबेल पुरस्कार विजेताओं और तीन अन्य प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। एक विस्तारित नवाचार प्रदर्शनी की भी योजना बनाई गई है, जिसमें सरकारी विभागों, गहन-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और विभिन्न नवाचार पहलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 150 तक स्टॉल शामिल होंगे। इस सम्मेलन से ज्ञान के आदान-प्रदान, तकनीकी सहयोग और अनुसंधान तथा नवाचार में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच उपलब्ध होने की उम्मीद है।

मुख्य बिंदु:

- अक्टूबर में सम्मेलन निर्धारित: ESTIC 2026 का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा।
- नोबेल पुरस्कार विजेताओं की भागीदारी की पुष्टि: तीन नोबेल पुरस्कार विजेताओं और तीन अन्य प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं ने आगामी विज्ञान सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।
- नवाचार प्रदर्शनी का विस्तार: प्रदर्शनी में सरकारी विभागों, गहन-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और नवाचार पहलों से जुड़े 150 तक स्टॉल शामिल होने की उम्मीद है।

ESTIC 2026 to Bring Together Scientists, Innovators and Three Nobel Laureates in New Delhi

✎ ESTIC 2026, an international science and technology conclave, is scheduled to be held from October 27 to 29 at



Bharat Mandapam in New Delhi. The event will bring together scientists, innovators, researchers and policymakers to promote collaboration in science and emerging technologies. Three Nobel Laureates and three other distinguished international award recipients have confirmed their participation. An expanded innovation exhibition is also planned, featuring up to 150 stalls representing government departments, deep-tech startups and various innovation initiatives. The conclave is expected to provide a platform for knowledge exchange, technological cooperation and showcasing India's growing capabilities in research and innovation.

Key Points:

- Conclave scheduled in October: ESTIC 2026 will be held from October 27 to 29 at Bharat Mandapam in New Delhi.
- Nobel participation confirmed: Three Nobel Laureates and three other distinguished international award recipients have confirmed participation in the upcoming science conclave.
- Innovation exhibition expanded: The exhibition is expected to feature up to 150 stalls involving government departments, deep-tech startups and innovation initiatives.

7. भारत ने 6G नेतृत्व और सुरक्षा के लिए कार्रवाई के आह्वान का समर्थन किया

भारत ने 6G नेतृत्व और सुरक्षा के लिए कार्रवाई के आह्वान का समर्थन किया है और 24 समान विचारधारा वाले देशों के साथ इसमें शामिल हुआ है, जो



खुले, अंतर-संचालनीय, सुरक्षित और लचीले अगली पीढ़ी के नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पहल की घोषणा उत्तरी कैरोलिना के चैपल हिल में आयोजित जी20 नवाचार मंत्रिस्तरीय बैठक के अवसर पर की गई। दूरसंचार विभाग सरकार की एजेंसियों, उद्योग, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के साथ भारत की आगे की भागीदारी का समन्वय करेगा। भारत का लक्ष्य वैश्विक 6G मानकों और पेटेंटों में 10 प्रतिशत योगदान देना है, जिससे अगली पीढ़ी के दूरसंचार में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की उसकी महत्वाकांक्षा मजबूत होगी। यह पहल सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं, साइबर सुरक्षा, अनुसंधान और विकास तथा अंतरराष्ट्रीय 6G मानकीकरण पर भी केंद्रित है।

मुख्य बिंदु:

- वैश्विक 6G साझेदारी: भारत ने 6G नेतृत्व और सुरक्षा के लिए कार्रवाई के आह्वान का समर्थन करने वाले 24 समान विचारधारा वाले देशों के साथ साझेदारी की।
- दूरसंचार विभाग नोडल एजेंसी: दूरसंचार विभाग सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के साथ भारत की भागीदारी का समन्वय करेगा।
- वैश्विक मानकों का लक्ष्य: भारत का लक्ष्य वैश्विक 6G मानकों और पेटेंटों में 10 प्रतिशत योगदान देना है, साथ ही सुरक्षित, लचीले और अंतर-संचालनीय नेटवर्क को बढ़ावा देना है।

India Endorses Call to Action for 6G Leadership and Security

India has endorsed the Call to Action for 6G Leadership and Security, joining 24 like-minded nations committed to



developing open, interoperable, secure and resilient next-generation networks. The initiative was announced on the sidelines of the G20 Innovation Ministerial held in Chapel Hill, North Carolina. The Department of Telecommunications will coordinate India's follow-up engagement with government agencies, industry, academia and other stakeholders. India aims to contribute 10 percent of global 6G standards and patents, strengthening its ambition to become a global leader in next-generation telecommunications. The initiative also focuses on secure supply chains, cybersecurity, research and development, and international 6G standardisation.

Key Points:

- Global 6G Partnership: India joined 24 like-minded nations in endorsing the Call to Action for 6G Leadership and Security.
- DoT as Nodal Agency: The Department of Telecommunications will coordinate India's engagement with government, industry, academia and other stakeholders.
- Global Standards Goal: India aims to contribute 10 percent of global 6G standards and patents, while promoting secure, resilient and interoperable networks.

8. बखिरा झील के तलछट मध्य गंगा मैदान में जल संसाधन प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं

✍ उत्तर प्रदेश की बखिरा झील पर 2026 में किए गए एक अध्ययन में लगभग 25,000 वर्षों के मानसून और जलवायु परिवर्तनों का पुनर्निर्माण



करने के लिए इसके तलछट का अध्ययन किया गया। तलछट अभिलेख कणों के आकार, खनिज संरचना और भू-रासायनिक विशेषताओं जैसे संकेतकों के माध्यम से मानसून की तीव्रता और जलवायु संबंधी परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्रदान करते हैं। बखिरा झील घाघरा-राप्ती नदी तंत्र से जुड़ी है और मध्य गंगा मैदान के आर्द्रभूमि परिदृश्य का हिस्सा है। यह अध्ययन दर्शाता है कि दीर्घकालिक तलछट अभिलेख तलछट परिवहन, बाढ़ और जलवायु परिवर्तनशीलता की समझ को बेहतर बना सकते हैं, जिससे क्षेत्र में अधिक सूचित जल-संसाधन प्रबंधन और योजना बनाने में सहायता मिल सकती है।

मुख्य बिंदु:

- दीर्घकालिक जलवायु अभिलेख: बखिरा झील के तलछट लगभग 25,000 वर्षों की पर्यावरणीय जानकारी को संरक्षित रखते हैं, जो मानसून की तीव्रता और जलवायु संबंधी परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों को दर्शाते हैं।
- मानसून के स्वरूप का पुनर्निर्माण: कणों का आकार, खनिज संरचना और भू-रासायनिक संकेतक भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की अधिक मजबूत और कमजोर गतिविधि की अवधियों की पहचान करने में सहायता करते हैं।
- जल प्रबंधन संबंधी जानकारी: तलछट अभिलेख तलछट परिवहन, बाढ़ के व्यवहार और जलवायु परिवर्तनशीलता की समझ को बेहतर बना सकते हैं, जिससे क्षेत्र में बेहतर जल-संसाधन योजना बनाने में सहायता मिलती है।

8. Sediments from Bakhira Lake May Support Water Resource Management in the Central Ganga Plain

✍ A 2026 study of Bakhira Lake in Uttar Pradesh examined its sediments to reconstruct around 25,000 years of monsoon



and climate variations. The sediment record provides insights into changes in monsoon intensity and hydroclimatic conditions through indicators such as grain size, mineral composition and geochemical characteristics. Bakhira Lake is associated with the Ghaghara-Rapti river system and forms part of the Central Ganga Plain's wetland landscape. The study highlights how long-term sediment records can improve understanding of sediment transport, flooding and climate variability, supporting more informed water-resource management and planning in the region.

Key Points:

- Long-term climate record: Bakhira Lake sediments preserve approximately 25,000 years of environmental information, revealing changes in monsoon intensity and hydroclimatic conditions.
- Monsoon patterns reconstructed: Grain size, mineral composition and geochemical indicators help identify periods of stronger and weaker Indian Summer Monsoon activity.
- Water management insights: Sediment records can improve understanding of sediment transport, flood behaviour and climate variability, supporting better water-resource planning in the region.

9. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने गैर-कॉरपोरेट गैर-कृषि क्षेत्र के लिए पहली बार जिला-स्तरीय अनुमान जारी किए

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत के गैर-कॉरपोरेट गैर-कृषि क्षेत्र के लिए पहली बार जिला-स्तरीय अनुमान



जारी किए हैं, जिससे देश की सांख्यिकीय प्रणाली मजबूत हुई है। संशोधित सर्वेक्षण रूपरेखा अधिक विस्तृत जिला-स्तरीय और त्रैमासिक अनुमानों को तैयार करने में सक्षम बनाती है, जिससे आर्थिक योजना और नीति निर्माण के लिए लगातार जानकारी उपलब्ध होती है। सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष 50 जिलों में इस क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन और कार्यबल का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। नया आँकड़ा सरकारों को स्थानीय आर्थिक गतिविधियों का अधिक प्रभावी ढंग से आकलन करने और विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए लक्षित नीतियाँ बनाने में सहायता कर सकता है। यह पहल पूरे भारत में क्षेत्रीय आर्थिक मापन और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु:

- जिला-स्तरीय आँकड़े प्रस्तुत: सांख्यिकीय प्रणाली को गैर-कॉरपोरेट गैर-कृषि प्रतिष्ठानों के लिए जिला-स्तरीय अनुमान तैयार करने हेतु मजबूत किया गया है, जिससे स्थानीय आर्थिक आकलन में सुधार होगा।
- त्रैमासिक अनुमान सक्षम: संशोधित सर्वेक्षण रूपरेखा त्रैमासिक अनुमान तैयार करने में सहायता करती है, जिससे योजना और नीति कार्यान्वयन के लिए अधिक लगातार जानकारी उपलब्ध होती है।
- बेहतर नीति निर्माण में सहायता: विस्तृत जिला-स्तरीय जानकारी सरकारों को कृषि से बाहर के विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए लक्षित नीतियाँ बनाने में सहायता कर सकती है।

NSO Releases First-Ever District-Level Estimates for Unincorporated Non-Agricultural Sector

The National Statistical Office has released the first-ever district-level estimates for India's unincorporated non-agricultural sector, strengthening the country's statistical system. The revised survey framework enables the generation of more detailed district-level and quarterly estimates, providing frequent information for economic planning and policy formulation. According to the September 2026 report, the top 50 districts account for nearly one-third of the sector's Gross Value Added and workforce. The new data can help governments assess local economic activity more effectively and design targeted policies for manufacturing, trade and service-sector establishments. The initiative marks an important step towards improving regional economic measurement and evidence-based policymaking across India.



Key Points:

- District-level data introduced: The statistical system has been strengthened to generate district-level estimates for unincorporated non-agricultural establishments, improving local economic assessment.
- Quarterly estimates enabled: The revised survey framework supports generation of quarterly estimates, providing more frequent information for planning and policy implementation.
- Better policymaking supported: Detailed district-level information can help governments formulate targeted policies for manufacturing, trade and service-sector establishments outside agriculture.

10. नीति आयोग ने अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए विनियमन में कमी की आवश्यकता पर जोर दिया

नीति आयोग ने व्यवसायों के लिए अनुमति मिलने तक प्रतिबंधित व्यवस्था से प्रतिबंधित होने तक अनुमति प्राप्त व्यवस्था की ओर बदलाव पर आधारित अगली पीढ़ी के सुधारों का आह्वान किया है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य अनावश्यक विनियमों को कम करना, अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाना और उद्यमों पर विनियामक बोझ को घटाना है। सुधार दृष्टिकोण अत्यधिक नियंत्रणों को सरल, पूर्वानुमेय और पारदर्शी प्रणालियों से बदलकर विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देना चाहता है। विनियामक बाधाओं को कम करके, इस पहल से कारोबार करने में सुगमता बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और अधिक आर्थिक दक्षता को समर्थन मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित रूपरेखा एक ऐसे अधिक सक्षम कारोबारी वातावरण का निर्माण करने के प्रयास को दर्शाती है, जहाँ कानून के तहत किसी विशिष्ट गतिविधि पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध न होने तक उद्यम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।



मुख्य बिंदु:

- विनियामक दृष्टिकोण में बदलाव: नीति आयोग ने व्यवसायों के लिए अनुमति मिलने तक प्रतिबंधित व्यवस्था से प्रतिबंधित होने तक अनुमति प्राप्त व्यवस्था की ओर बढ़ने की वकालत की है।
- अनुपालन का बोझ कम: प्रस्तावित सुधार अनावश्यक विनियमों को हटाने और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे उद्यम अधिक कुशलता से कार्य कर सकें।
- विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा: अगली पीढ़ी के सुधार विनियामक बाधाओं को कम करने, निवेश को प्रोत्साहित करने और अत्यधिक नियंत्रणों को सरल, पूर्वानुमेय अनुपालन प्रणालियों से बदलने पर जोर देते हैं।



10. NITI Aayog Calls for Deregulation to Drive Next-Generation Reforms

NITI Aayog has called for next-generation reforms based on a shift from a prohibited-unless-permitted framework to a permitted-unless-prohibited approach for businesses. The proposed changes aim to reduce unnecessary regulations, simplify compliance requirements and lower the regulatory burden on enterprises. The reform approach seeks to promote trust-based governance by replacing excessive controls with simpler, predictable and transparent systems. By reducing regulatory friction, the initiative is expected to improve the ease of doing business, encourage investment and support greater economic efficiency. The proposed framework reflects an effort to create a more enabling business environment where enterprises can operate freely unless specific activities are expressly restricted under law.



Key Points:

- Regulatory approach shifted: NITI Aayog has advocated moving from a prohibited-unless-permitted framework towards a permitted-unless-prohibited approach for businesses.
- Compliance burden reduced: Proposed reforms seek to remove unnecessary regulations and simplify business processes, enabling enterprises to operate more efficiently.
- Trust-based governance promoted: Next-generation reforms emphasise reducing regulatory friction, encouraging investment and replacing excessive controls with simpler, predictable compliance systems.



दैनिक समसामयिक

DAILY

CURRENT AFFAIRS



MCQs प्रश्नोत्तरी

Q1. नीति आयोग ने विनियामक अनुमोदनों की व्यवस्था में किस मूल सिद्धांत की ओर बदलाव का प्रस्ताव दिया है?

- (a) अनुमति मिलने तक प्रतिबंधित
- (b) प्रतिबंधित होने तक अनुमति प्राप्त
- (c) शुरुआत से पहले अनुपालन
- (d) सभी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस अनिवार्य

Q2. सितंबर 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शीर्ष 50 जिलों में गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन और कार्यबल कालगभग कितना हिस्सा है?

- (a) दसवाँ हिस्सा
- (b) एक-तिहाई
- (c) आधा
- (d) दो-तिहाई

Q3. 2026 में बखिरा झील के तलछट पर किए गए अध्ययन के अनुसार, बखिरा झील किस नदी तंत्र से जुड़ी है?

- (a) यमुना-चंबल तंत्र
- (b) घाघरा-राप्ती तंत्र
- (c) कोसी-महानंदा तंत्र
- (d) सोन-रिहंद तंत्र

Q4. भारत ने 6G नेतृत्व और सुरक्षा के लिए कार्रवाई के आह्वान का समर्थन कितने समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर किया है?

- (a) 14
- (b) 20
- (c) 24
- (d) 30

Q5. ESTIC 2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में कहाँ किया जाना निर्धारित है?

- (a) यशोभूमि सम्मेलन केंद्र
- (b) सुषमा स्वराज भवन
- (c) विज्ञान भवन
- (d) भारत मंडपम

Q1. Which fundamental principle has NITI Aayog proposed to shift towards in the system of regulatory approvals?

- (a) Restricted until permission is granted
- (b) Permitted unless prohibited
- (c) Compliance before commencement
- (d) Licensing mandatory for all sectors

Q2. According to the National Statistical Office report released in September 2026, approximately what share of the Gross Value Added and workforce of the non-corporate sector in India is accounted for by the top 50 districts?

- (a) One-tenth
- (b) One-third
- (c) Half
- (d) Two-thirds

Q3. According to a study conducted on the sediments of Lake Bakhira in 2026, Lake Bakhira is connected to which river system?

- (a) Yamuna-Chambal system
- (b) Ghaghara-Rapti system
- (c) Kosi-Mahananda system
- (d) Son-Rihand system

Q4. India joined how many like-minded countries in supporting the call for action on 6G leadership and security?

- (a) 14
- (b) 20
- (c) 24
- (d) 30

Q5. Where is the ESTIC 2026 International Conference scheduled to be held in New Delhi?

- (a) Yashobhoomi Convention Centre
- (b) Sushma Swaraj Bhawan
- (c) Vigyan Bhawan
- (d) Bharat Mandapam

- Q6. झारखंड में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सहायता प्रदान करने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को नामित किया गया है?
- (a) रेलटेल कॉरपोरेशन
(b) पावरग्रिड कॉरपोरेशन
(c) बीएसएनएल
(d) टीसीआईएल
- Q7. सितंबर 2026 में NIELIT और अमेरिका स्थित सेयलर विश्वविद्यालय के बीच साझेदारी के अंतर्गत एनडीयू मंच पर किन प्रमुख क्षेत्रों में निःशुल्क, अपनी गति से पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे?
- (a) कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और व्यवसाय प्रबंधन
(b) वस्त्र प्रौद्योगिकी और परिधान अभिकल्पना
(c) पेट्रोलियम अभियांत्रिकी और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
(d) एयरोस्पेस गतिकी और समुद्री नौवहन
- Q8. सितंबर 2026 में कृषि और वानिकी पर 9 वें आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की सह-अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किस देश के कृषि सचिव ने की?
- (a) वियतनाम (b) इंडोनेशिया
(c) फिलीपींस (d) थाईलैंड
- Q9. सितंबर 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी रेलवे बहु-पटरी परियोजनाओं को मंजूरी दी?
- (a) दो (b) तीन
(c) चार (d) पाँच
- Q10. सितंबर 2026 में अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियमों में संशोधन औपचारिक रूप से किस तारीख से लागू होंगे?
- (a) 1 अक्टूबर 2026 (b) 1 जनवरी 2027
(c) 31 मार्च 2027 (d) 1 अप्रैल 2026

- Q6. Which public sector undertaking has been designated to provide Project Management Consultancy support for the implementation of the revamped BharatNet programme in Jharkhand?
- (a) RailTel Corporation
(b) Power Grid Corporation
(c) BSNL
(d) TCIL
- Q7. Under the partnership finalized between NIELIT and the US-based Saylor University in September 2026, in which major areas will learners have access to free, self-paced courses on the NDU platform?
- (a) Artificial Intelligence, Cybersecurity and Business Management
(b) Textile Technology and Apparel Design
(c) Petroleum Engineering and Geological Surveying
(d) Aerospace Dynamics and Maritime Navigation
- Q8. In September 2026, the 9th ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry was co-chaired by Union Minister Shivraj Singh Chouhan and the Agriculture Secretary of which country?
- (a) Vietnam (b) Indonesia
(c) Philippines (d) Thailand
- Q9. In September 2026, the Union Cabinet approved how many railway multi-tracking projects?
- (a) Two (b) Three
(c) Four (d) Five
- Q10. The amendments to the Consumer Protection (E-Commerce) Rules, notified in September 2026, will formally come into effect from which date?
- (a) 1 October 2026 (b) 1 January 2027
(c) 31 March 2027 (d) 1 April 2026

उत्तरमाला (Answer Key)

- 1 B 2 B 3 B 4 C 5 D 6 C 7 A 8 C 9 D 10 B

